



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]
No. 113|नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 30, 2012/वैशाख 10, 1934
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 30, 2012/VAISAKHA 10, 1934

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2012

फा. सं. 1-9/2012 बीएंडसीएस.—भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना सं. 39 जो,—

(ए) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(बी) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 में अधिसूचना दिनांक 9 जनवरी, 2004 की संख्या का.आ. 44(अ) और 45(अ) के तहत प्रकाशित हुई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (2) और उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंडों (ii), (iii), (iv) और (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चतुर्थ) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ आदेश, 2010 (2010 का 1) में आगे संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (चतुर्थ) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (प्रथम संशोधन) आदेश, 2012
(2012 का 3)

1. (1) इस आदेश को "दूरसंचार (बॉडकॉस्टिंग तथा केबल) सेवाएं (चतुर्थ) एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (प्रथम संशोधन) आदेश, 2012 (2012 का 3)" कहा जाएगा।

(2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चतुर्थ) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ आदेश, 2010 (2010 का 1) (जिसे यहां इसके बाद मूल टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड 2 में को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“अनुप्रयोज्यता—यह आदेश संपूर्ण भारत के शासित क्षेत्र में उपभोक्ताओं को डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई जा रही प्रसारण सेवाओं एवं केबल सेवाओं पर लागू होगा।”

3. मूल टैरिफ आदेश के खंड 3 में,—

(ए) उपखंड (बी) के बाद निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(बी) “एड्रेसेबल प्रणाली” से आशय है एक इलैक्ट्रानिक उपकरण (जिसमें हार्डवेयर और इससे सम्बद्ध साफ्टवेयर शामिल हैं) अथवा एक से अधिक इलैक्ट्रानिक उपकरण, जिन्हे एकीकृत प्रणाली में रखा गया हो और जिनके माध्यम से सिग्नल कूट (एनक्रिप्टिड) रूप में भेजे जा सकते हैं और, जिन्हे उपभोक्ता को मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर या आईपीटीवी ऑपरेटर या एचआईटीएच ऑपरेटर द्वारा उपभोक्ता की स्पष्ट पसंद व अनुरोध पर, कन्डीशनल एक्सेस प्रणाली और उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्राधिकृत सीमाओं के भीतर, उपभोक्ता के परिसर में सक्रिय कन्डीशनल एक्सेस वाले किसी उपकरण अथवा उपकरणों से कूटानुवाद (डिकोड) किया जा सकता है।”

(बी) उपखंड (ई) के बाद निम्नलिखित उपखंड अन्तस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ईए) “बुनियादी सेवा टियर” से आशय है केबल ऑपरेटर द्वारा पेश किए जाने वाले फ्री-टु-एयर चैनलों का एक पैकेज, जिसमें जिस क्षेत्र में उसके केबल टेलीविजन नेटवर्क द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है, के उपभोक्ता को एकल मूल्य पर अभिदान करने का विकल्प होगा।”

(सी) उपखंड (एम) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(एम) “केबल ऑपरेटर” से आशय है कोई ऐसा व्यक्ति जो केबल टेलीविजन नेटवर्क केबल सेवा उपलब्ध कराता है या अन्यथा नियंत्रण के जरिए जो किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए जिम्मेदार है तथा निर्धारित पात्रता के मापदंड और शर्तें पूरी करता है।

(डी) उपखंड (एस) के बाद निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(एसए) केबल टेलीविजन नेटवर्क के किसी सिगनल के संबंध में “एनक्रिप्टेड” से आशय है एक व्यवस्थित तरीके से उस सिगनल को बदलना ताकि वह सिगनल एड्रेसेबल प्रणाली का इस्तेमाल किए बिना अबोधगम्य हो जाएगा और “अनएनक्रिप्टेड” अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार होगा;

(ई) उपखंड (एक्स) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(एक्स) “मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)” से आशय है कोई ऐसा ऑपरेटर जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11, जिसे कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधित) नियम, 2012 के नियम 8 द्वारा संशोधित किया गया है, के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान किया गया है और जो किसी प्रसारक या इसकी प्राधिकृत एजेंसियों से कोई कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है और मल्टीपल उपभोक्ताओं द्वारा सीधे ही अथवा एक या अधिक रक्तानीय केबल ऑपरेटर(एलसीओ) के माध्यम से, साथ-साथ प्राप्त करने के लिए, इन्हें या तो री-ट्रांसमिट करता है अथवा अपनी स्वयं की कार्यक्रम सेवा को ट्रांसमिट करता है, और इसमें उसकी प्राधिकृत वितरण एजेंसिया सम्मिलित है, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए;

(एफ) उपखंड (जेडए) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(जेडए) “पे चैनल” से आशय है डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के संबंध में उन चैनलों से जिसके लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर या आईपीटीवी ऑपरेटर या एचआईटीएस ऑपरेटर द्वारा प्रसारक को अभिदान शुल्क का भुगतान किया जाना है तथा प्रसारकों से डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली पर उसके री-ट्रांसमिशन हेतु पर्याप्त अधिकृत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है ।

(जी) उपखंड (जेडबी) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(जेडबी) “प्रोग्राम” से आशय है कोई टेलीविजन प्रसारण और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) फिल्मों, फीचरों, ड्रामा, विज्ञापनों और धारावाहिकों का प्रदर्शन;
- (ii) कोई आडियो या विजुअल या ऑडियो-विजुअल लाइव प्रस्तुतिकरण या प्रस्तुति और “कार्यक्रम सेवा” अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार होगा;

(एच) उपखंड (जेडई) में "पे" शब्द को हटा दिया जाएगा।

(आई) उपखंड (जेडई) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

अर्थात्:-

"(जेडई)"सब्सक्राइबर" से आशय है कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ अथवा कोई कंपनी, अथवा अन्य संगठन या निकाय, जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा डीटीएच ऑपरेटर अथवा आईपीटीवी ऑपरेटर अथवा एचआईटीएस ऑपरेटर के सिग्नल, उसके अथवा उनके द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा डीटीएच ऑपरेटर अथवा आईपीटीवी ऑपरेटर अथवा एचआईटीएच ऑपरेटर को निर्दिष्ट किए गए स्थान पर प्राप्त करता है और इनका आगे संप्रेषण नहीं करता है, और इसमें सामान्य सब्सक्राइबर और व्यावसायिक सब्सक्राइबर, जब तक कि इन्हें विशिष्ट रूप से अलग न किया गया हो, सम्मिलित है;"

(जे) उपखंड (जेडई) के बाद निम्नलिखित उपखंड को अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(जेडईए)"सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली" से आशय किसी ऐसी प्रणाली अथवा साधन से है, जो सब्सक्राइबर के नाम पते और सब्सक्राइबर द्वारा उपयोग में लाई जा रही हार्डवेयर, सब्सक्राइबर द्वारा अभिदत चैनलों अथवा चैनलों के बुकेसमूह), प्रणाली में विनिर्दिष्ट अनुसार ऐसे चैनलों अथवा चैनलों के बुकेसमूह) का मूल्य, किसी चैनल अथवा चैनलों बुकेसमूह) के एकटीवेशन अथवा डी-एकटीवेशन की तिथियां व समय, सब्सक्राइबर के रिकार्ड पर निष्पादित समस्त कार्रवाइयों का लॉग, प्रत्येक सब्सक्राइबर पर जनित इन्वाइस और भुगतान की गई राशि अथवा प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए सब्सक्राइबर को दी गई छूट के संबंध में सब्सक्राइबर के रिकार्ड को संचित करती है;"

4. मूल टैरिफ आदेश के खंड 5 में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यदि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच सहमति न हो पाए तो सब्सक्रिप्शन से प्राप्त किए जाने वाले प्रभार को निम्नलिखित तरीके से विभाजित किया जाएगा:-

(ए) बुनियादी सर्विस टियर के चैनलों, फ्री-टु-एयर चैनल तथा फ्री-टु-एयर चैनलों के समूहों के सब्सक्रिप्शन से प्राप्त होने वाले प्रभार को 55:45 के अनुपात में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच बॉटा जाएगा, और

(बी) खंड (ए) में उल्लिखित चैनलों से इतर चैनलों अथवा चैनलों के बुके(समूह) अथवा चैनलों और चैनलों के बुके(समूह) के सब्सक्रिप्शन से प्राप्त होने वाले प्रभार को 65:35 के अनुपात में क्रमशः मल्टी सिस्टम ऑपरेटर व स्थानीय केबल ऑपरेटर के मध्य बॉटा जाएगा ।

5. मूल टैरिफ आदेश के खण्ड 6 में उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर या आईपीटीवी ऑपरेटर या एचआईटीएस ऑपरेटर, जो इस आदेश के लागू होने की तारीख से एड्रेसेबल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए अपने सब्सक्राइबरों को प्रसारण सेवाएं अथवा केबल सेवाएं मुहैया कराता है, वह अ—ला—कार्ट आधार पर अपने सब्सक्राइबरों को सभी चैनल की पेशकश करेगा अथवा पेशकश करवाएगा और वह प्रत्येक चैनल के लिए एक सामान्य सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान की जाने वाली अधिकतम फुटकर कीमत भी निर्धारित करेगा” ।

बशर्ते कि फ्री-टु-एयर चैनलों की अ—ला—कार्ट दरें एक समान होगी” ।

6. मूल टैरिफ आदेश के खंड 6 में, ---

(ए) उपखंड (1) में प्रथम प्रावधान के बाद निम्नलिखित प्रावधान जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

“बशर्ते यह भी कि कोई मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर या आईपीटीवी ऑपरेटर या एचआईटीएस ऑपरेटर, जो अपने सब्सक्राइबरों को डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली का प्रयोग करते हुए प्रसारण सेवाएं अथवा केबल सेवाएं मुहैया कराता है, वह चैनलों को पेशकश बुके(समूह) के भाग के रूप में करता है तो उस बुके (समूह) के भाग के रूप ऐसे चैनलों की दर निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्धारित की जाएगी, अर्थात्:—

(ए) ऐसे बुके(समूह) में शामिल सभी चैनलों के अ—ला—कार्ट दरों का योग, बुके की दर से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगा, और

(बी) ऐसे समूह के भाग वाले प्रत्येक चैनल की अ-ला-कार्ट दर किसी भी स्थिति में उस समूह, जिसका कि चैनल भाग है, की औसत दर के तीन गुणा से ज्यादा नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर या आईपीटीवी ऑपरेटर या एचआईटीएस ऑपरेटर जो इस टैरिफ आदेश के लागू करने की तारीख से पहले डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टमों के माध्यम से प्रसारण सेवाएं तथा केबल सेवाएं मुहैया करा रहा हो तथा इसके लागू हो जाने के बाद भी ऐसी सेवाएं मुहैया कराना जारी रखे हुए हो, वह इसके लागू होने के 60 दिन के भीतर, द्वितीय प्रावधान के उपबंधों का पालन करेगा।"

(बी) उपखंड (1) के बाद निम्नलिखित 'उपखंड जोड़ा जाएगा, अर्थातः—

"(1ए) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर जो डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए सीधे अथवा लिंक्ड लोकल केबल ऑपरेटर के माध्यम से सब्सक्राइबरों को केबल सेवाएं मुहैयां कराता हो। बुनियादी सेवा टियर के रूप में कम से कम एक सौ फ्री-टु-एयर चैनलों के पैकेज की पेशकश करेगा जिसमें प्रसार भारती के चैनल जैसे कि डीडी-भारती, डीडी-मलयालम, डीडी-पोथिगई, डीडी-ओडिया, डीडी-बांग्ला, डीडी-सप्तगिरि, डीडी-चंदना, डीडी- सहयाद्रि, डीडी- गिरनार, डीडी-कशीर, डीडी-एनई, डीडी-पंजाबी सम्मिलित होंगे।"

(1बी) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा पेश किए गए बुनियादी सेवा टियर के बदले में एक सौ चैनलों तथा फ्री-टु-एयर चैनलों के किसी संयोजन को चुनने के लिए सब्सक्राइबर स्वतंत्र होगा।

बशर्ते कि, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, बेसिक सेवा टियर के लिए अथवा सब्सक्राइबर द्वारा बेसिक टियर के एवज में चुने गए फ्री-टु-एयर चैनलों के लिए, प्रति सब्सक्राइबर एक सौ रूपए तक(कर रहित) न्यूनतम मासिक अभिदान विनिर्दिष्ट करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(1सी) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा पेश किए जाने वाले बुनियादी सेवा टियर में प्रत्येक श्रेणी जैसे कि समाचार, करंट अफेयर, ज्ञानरंजन, खेलकूद, बच्चों के कार्यक्रम, संगीत, लाइफस्टाइल, मूवीज तथा हिंदी, अंग्रेजी तथा उस क्षेत्र की

क्षेत्रीय भाषा में सामान्य मनोरंजन के कम से कम पांच चैनल शामिल किए जाएंगे।

बशर्ते कि यदि किसी श्रेणी के वर्धाप्त फ्री-टु-एयर चैनल उपलब्ध न हों तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, बुनियादी सर्विस टियर में अन्य श्रेणियों के चैनलों को शामिल करेगा।

- (1डी) डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम केबल टीवी प्रणाली के माध्यम से केबल सेवाएं मुहैया कराने वाले सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबर, केवल बुनियादी सेवा टियर अथवा बुनियादी सेवा टियर और एक या अधिक पे चैनल अथवा केवल फ्री-टु-एयर चैनल अथवा केवल पे चैनलों अथवा पे चैनल तथा फ्री-टु-एयर चैनलों को चुन सकेंगे।
- (1ई) यदि कोई डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सब्सक्राइबर पे चैनलों को फ्री-टु-एयर चैनल के साथ अथवा इसके बिना, अ-ला-कार्ट या बुके या अ-ला-कार्ट एवं बुके चैनलों के मिश्रण के साथ सब्सक्राइब करता है तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर न्यूनतम मासिक सब्सक्रिप्शन निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा, जो प्रतिमाह अधिकतम एक सौ पचास रुपए (कर रहित) तक हो सकता है।"
- (सी) उपखंड(4) के बाद निम्नलिखित प्रावधान अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“बशर्ते कि उपखंड (4) का कोई भी प्रावधान डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली के सब्सक्राइबरों पर लागू नहीं होगा”

7. मूल टैरिफ आदेश के खंड 8 में उपखंड (1) में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यदि सब्सक्रिप्शन पैकेज के भाग वाले किसी फ्री-टु-एयर चैनल को ब्रॉडकास्टर द्वारा पे चैनल में बदला जाता है तो सब्सक्राइबर की ऐसी सहमति जिसे सत्यापित किया जा सकता है के आधार पर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर या आईपीटीवी ऑपरेटर या एचआईटीएस ऑपरेटर, ऐसे सब्सक्राइबर के सब्सक्रिप्शन पैकेज से उक्त चैनल को या तो हटा सकता है और सब्सक्रिप्शन पैकेज की कीमत में ऐसे फ्री-टु-एयर चैनल की अ-ला-कार्ट कीमत के बराबर राशि को कम कर सकता है अथवा सब्सक्रिप्शन पैकेज की कीमत को बढ़ा सकता है, परंतु यह वृद्धि ऐसे फ्री-टु-एयर चैनल की अ-ला-कार्ट चैनल को बदलने के बाद इसी अ-ला-कार्ट कीमत के बीच के अंतर से ज्यादा नहीं होगी।

8. मूल टैरिफ आदेश के खंड 9 में, -

“(ए) उपखंड (5) में ‘पे’ शब्द हो हटा दिया जाएगा;

(बी) उपखंड (5) के उपरांत निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

बशर्ते आगे यह भी कि, इस प्रकार के प्रत्येक ऑपरेटर, जो इस टैरिफ आदेश के लागू हो जाने के बाद अपनी सेवाएं प्रारंभ करता है वह प्राधिकरण को अपनी सेवा प्रारंभ करने से पूर्व ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा तत्पश्चात् दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने से कम से कम 30 दिन पहले सूचित करेगा।”

कसी अहमद, सलाहकार

[विज्ञापन III/4/142/12/असा.]

नोट :- इस आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चौथा) (डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (प्रथम संशोधन) आदेश, 2012 (2012 का 3) के उद्देश्य तथा कारणों की व्यवस्था की गई है।

अनुबंध

व्याख्यात्मक ज्ञापन

I. पृष्ठभूमि

1. पिछले कुछ वर्षों में टीवी चैनलों (फ्री-टु-एयर और पे दोनों में) की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के साथ-साथ एनालॉग केबल टीवी प्रणालियों की अंतर्निहित सीमाओं में भी केबल टीवी सेक्टर में अनेक चुनौतियां सामने आई हैं, मुख्यतः क्षमता संबंधी बाधाओं और नेटवर्क के गैर एड्रेसेबल स्वरूप के कारण। समय और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ नए एड्रेसेबल डिजिटल टीवी मंच जैसे डीटीएच, आईपीटीवी आदि जनता को उपलब्ध करा दिए गए थे। प्रौद्योगिक विकास ने भी केबल टीवी सेक्टर में डिजिटाइजेशन के साथ एड्रेसेब्लिटी लाने हेतु मार्ग प्रशस्त किया है। तदनुसार इस विषय का गहनता से अध्ययन करने और परामर्श प्रक्रिया अपनाने के पश्चात प्राधिकरण ने दिनांक 05 अगस्त, 2010 को इसे प्राप्त करने हेतु एक रोडमैप के साथ-साथ पूरे देश में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली (डीएएस) के कार्यान्वयन पर अपनी सिफारिशें दी थीं।
2. भारत में एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली के कार्यान्वयन को लागू करने के लिए दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 को सरकार द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम), अधिनियम, 1995 में संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी किया गया। इसके पश्चात् सरकार द्वारा दिनांक 11 नवंबर, 2011 को अधिसूचना जारी की गई, जिसमें जून, 2012 से दिसम्बर, 2014 तक चरणबद्ध रूप में चार चरणों में कार्यान्वयन करने की रूपरेखा निर्धारित की गई। इसके उपरांत, दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 का अध्यादेश, दिसम्बर, 2011 में अधिनियम बन गया। उक्त संशोधन अधिनियम, अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त, डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली के ऑपरेटरों द्वारा पेशकश किए जाने वाले बुनियादी सेवा टियर (बीएसटी) की संरचना एवं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित टैरिफ उपलब्ध कराता है।
3. पूर्व में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 21 जुलाई 2010 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणालिया) टैरिफ आदेश, 2010 जारी किया था जिसमें समूचे भारत क्षेत्र में, अधिसूचित कैस-क्षेत्रों में केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से प्रदान कराई गई केबल सेवाओं को छोड़कर, सब्सक्राइबरों को एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराई गई

प्रसारण और केबल सेवाओं पर लागू किया गया था। केबल टेलीविजन नेटवर्क(विनियम) संशोधित अधिनियम, 2011 के प्रावधानों एवं उपर्युक्त वर्णित दिनांक 11/11/2011 की अधिसूचना पर विचार करते हुए, उक्त टैरिफ आदेश में निर्धारित टैरिफ शर्तों में उपर्युक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकरण द्वारा डिजिटल एड्सेबल केबल टीवी प्रणाली को लागू करने से संबंधित मुद्दों पर परामर्श प्रक्रिया आरम्भ की गई। परामर्श प्रक्रिया में, अंतःसंयोजन एवं सेवा की गुणवत्ता से संबंधित अन्य मुद्दों के अतिरिक्त, बुनियादी सेवा टियर (बीएसटी) की संरचना एवं टैरिफ, खुदरा टैरिफ, मुफ्त चैनलों में विज्ञापन हेतु टैरिफ एवं मल्टी सिस्टम ऑपरेटर(एमएसओ) एवं स्थानीय केबल ऑपरेटरों(एलसीओ) के बीच आय सहभाजन से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

- इस संबंध में, दिनांक 22/12/2011 को “डिजिटल एड्सेबल केबल टीवी प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर” परामर्श पत्र जारी किया गया। दिनांक 22 दिसम्बर 2011 को जारी परामर्श-पत्र के प्रत्युत्तर में उपभोक्ताओं सहित हितधारकों से कुल 87 टिप्पणियां और 4 प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुईं। तदनुसार, 13 मार्च 2012 को भी एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई जहां सभी उपस्थित हितधारकों के साथ इन मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया। हितधारकों की टिप्पणियों/रायों तथा विश्लेषण के आधार पर, बीएसटी के टैरिफ और संरचना, खुदरा टैरिफ, विज्ञापन-मुक्त चैनलों के लिए टैरिफ तथा एमएसओ और एलसीओ के बीच राजस्व हिस्से के संबंध में विभिन्न उपबंधों का आकलन किया गया है और, तदनुसार इस संशोधित टैरिफ आदेश के द्वारा टैरिफ आदेश में संशोधन किया गया है।

II. मुद्दों का विश्लेषण

ए. बुनियादी सेवा टियर

- अनेक हितधारकों ने सुझाव दिया कि बीएसटी के लिए उपबंध करने के स्थान पर दिनांक 21 जुलाई 2010 के टैरिफ आदेश में पहले से ही उपलब्ध शर्ते डीएस क्षेत्रों के लिए दोहराई जानी चाहिए क्योंकि ये उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। उक्त उपबंध किसी एड्सेबल टीवी प्लेटफार्म के प्रचालक को किसी उपभोक्ता द्वारा पसंद किए गए चैनल के लिए अ-ला-कार्ट या बुकेसमूह आधार पर एक न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्रभार निर्दिष्ट करने की अनुमति प्रदान करता है जो प्रति सब्सक्राइबर प्रतिमाहर 150 रु० से अधिक नहीं होगा। अपनी राय के समर्थन में हितधारकों ने कहा है कि विशेष रूप

से ग्रामीण क्षेत्रों और केबल विहीन क्षेत्रों में डीटीएच की अत्यधिक तेज वृद्धि स्पष्ट रूप से यह बात सिद्ध करती है कि बाजार की ताकंतों ने पैकेजिंग और मूल्य-निर्धारण, दोनों ही के संदर्भ में खुदरा स्तर पर अत्यंत बेहतर रूप से कार्य किया है। जहां तक अनिवार्य लोक सेवाओं का संबंध है, कुछ सेवा प्रदाताओं ने कहा है कि लोक प्रसारकों की सेवाएं बिना किसी पुनःआवर्ती प्रभारों के अपनी स्थानिक सेवाओं और डीटीएच प्लेटफार्म (डीडी डायरेक्ट प्लस) के माध्यम से एफटीए चैनलों के रूप में समूचे भारत में बुनियादी टेलीविजन सेवाओं के लिए जनता की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

6. केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2011 की धारा 4ए में, बुनियादी सेवा टियर (बीएसटी) में ऐसे क्षेत्र, जिसमें उसका केबल टेलीविजन नेटवर्क सेवाएं प्रदान कर रहा है, के उपभोक्ताओं को एकल कीमत पर अभिदान करने के एक विकल्प के साथ, एक उपभोक्ता को केबल ऑपरेटर द्वारा पेश किए जाने वाले फ्री-टु-एयर चैनलों के पैकेज का प्रावधान है। उपभोक्ता को बीएसटी के लिए अभिदान करने का विकल्प है। बीएसटी का गठन और टैरिफ भादूविप्रा द्वारा तय किया जाना है। इस प्रकार टैरिफ आदेश में बीएसटी से संबंधित आदेश का प्रावधान है।
7. जहां तक बीएसटी के आकार और दर का संबंध है, हितधारकों द्वारा विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया है। जिन हितधारकों ने बीएसटी के आकार का सुझाव दिया है, उनमें से अधिकांश हितधारकों ने इसे 30 से 70 चैनलों की परिधि में रखा है और इसका मूल्य 60 रु0 से 150 रु0 के बीच में सुझाया है। कुछ हितधारकों ने स्लैबवार बीएसटी उपायों का सुझाव दिया है, जो 30 चैनलों के लिए 82 रु0 तथा 100 चैनलों से अधिक के लिए 150 रु0 के बीच में है। कुछ अन्य हितधारकों ने यह भी सुझाव दिया है कि चूंकि भारत मानव-जातीयता, भाषा, प्राथमिकताओं, पसंद और विकल्पों के संबंध में एक विविधतापूर्ण देश है, यह उचित होगा कि आकार को तथा इसकी दर को प्राधिकरण द्वारा परिभाषित किए जाने के स्थान पर प्रचालकों द्वारा निर्णय करने के लिए छोड़ दिया जाए। एक सुझाव यह था कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अनुरूप, जहां प्रचालकों द्वारा थोपे गए विनियमों के बिना 70-80 चैनल प्रदान किए जा रहे हैं, उसी प्रकार, भारत में भी अन्य प्लेटफार्मों में की जाने वाली पेशकशें डीएस प्रचालक को बीएसटी के लिए एक प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव प्रदान करने के लिए बाध्य करेगी।
8. अधिसूचित कैस-क्षेत्रों के लिए लागू वर्तमान उपबंधों के अनुसार, बीएसटी का निर्माण करने वाले चैनलों के पैकेज में न्यूनतम तीस एफटीए चैनल शामिल किए जाते हैं, जिनकी आपूर्ति केबल प्रचालक को

उनके केवल नेटवर्क के सभी उपभोक्ताओं को प्रति सक्सक्राइबर प्रतिमाह 82 रु0 (करों को छोड़कर) की अधिकतम राशि पर की जानी आवश्यक है। गैर-कैस क्षेत्रों में, भादूविप्रा के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 01 अक्टूबर 2004 के टैरिफ आदेश के अनुसार, यदि प्रचालक केवल एफटीए चैनल उपलब्ध कराता है, तो इन्हें सब्सक्राइबर को न्यूनतम 30 एफटीए चैनलों के लिए प्रतिमाह 82 रु0 प्रति सब्सक्राइबर (करों को छोड़कर) उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तथापि, टैरिफ आदेश ऐसे प्रत्येक बंडल्ड पैकेजों में अनिवार्यतः शामिल किए गए न्यूनतम 30 एफटीए चैनलों के आधार पर बंडल्ड पैकेजों (पे और एफटीए चैनलों के लिए) के लिए स्लैबवार सब्सक्रिप्शन दरों की सीमा विनिर्दिष्ट करता है। इसी प्रकार, मसौदा टैरिफ आदेश में, जो गैर-कैस क्षेत्रों से संबंधित टैरिफ मुददों पर व्यापक रिपोर्ट का भाग है, जिसे भादूविप्रा द्वारा 21 जुलाई 2010 को माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया गया था, समूचे देश में बंडल्ड पेशकशों के लिए तीन समान उच्चतमांक(सीलिंग) को विनिर्दिष्ट किया गया है जिसमें न्यूनतम 30 एफटीए चैनल प्रत्येक बंडल्ड पेशकश में शामिल किए जाने अनिवार्य हैं। दर की सीलिंग न्यूनतम 30 एफटीए चैनलों के लिए 100 रु0 रखी गई है, यदि प्रचालक उपभोक्ता को केवल एफटीए चैनल प्रदान करता है। इसके अलावा, उक्त सभी टैरिफ शर्तों में, 30 चैनलों की अनिवार्य न्यूनतम सीमा के परे, कोई भी एफटीए चैनल उपभोक्ता को बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के उपलब्ध कराया जाना है।

9. यह सत्य है कि डिजिटलीकरण चैनल संचारित करने की क्षमता की बाधा को दूर करने में सहायता करता है। जबकि एनालॉग मोड में, 7 मेगा हर्ट्ज/8 मेगा हर्ट्ज चैनल में केवल एक ही चैनल संचारित किया जा सकता है, वहीं डिजिटल मोड में, नियोजित कम्प्रैशन और मोड्यूलेशन तकनीकों के आधार पर 7 मेगा हर्ट्ज/8 मेगा हर्ट्ज चैनल में 10-15 चैनल संचारित किए जा सकते हैं। इसके अलावा, बाजार में अब अधिक चैनल उपलब्ध हैं। तदनुसार, यह आशा की जा सकती है कि बीएसटी को पूर्व में अधिदेशित किए गए चैनलों की तुलना में चैनलों की अधिक संख्या को शामिल करना चाहिए। तथापि, अधिक चैनलों का समावेश स्वाभाविक रूप से बीएसटी की लागत को बढ़ाएगा। इसके अलावा, बड़ी मात्रा में बीएसटी विनिर्दिष्ट करने से अन्य पेशकशों को संचारित करने का लचीलापन कम हो जाएगा। अतः बीएसटी का आकार तथा दर निर्धारित करते समय एक संतुलित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, प्राधिकरण ने निर्दिष्ट किया है कि डिजिटल एड्रेसेबल केवल टीवी प्रणालियों के सभी प्रचालकों द्वारा 100 रु0 (करों को छोड़कर) की न्यूनतम राशि पर बीएसटी के रूप में न्यूनतम 100 एफटीए चैनल प्रदान किए जाएं।

10. बीएसटी की संरचना के मुद्दे पर, बड़ी संख्या में हितधारकों का यह मत है कि बीएसटी को विभिन्न विषय-वस्तुओं के चैनलों का मिश्रण होना चाहिए तथा उसकी संख्या को प्रचालन के स्थानीय क्षेत्र में सम्बन्धित बाजार की पसंद, वरीयता और आवश्यकता के अनुरूप बाजार की ताकतों द्वारा उस पर निर्णय लेने के लिए छोड़ देना चाहिए तथा बीएसटी का निर्माण करते समय क्षेत्रीय चैनलों को वरीयता दी जानी चाहिए। प्राधिकरण का यह मत है कि प्रचालकों को प्रत्येक विषय-वस्तु में से न्यूनतम पांच चैनल उपलब्ध कराते हुए विभिन्न विषय-वस्तुओं का एक औचित्यपूर्ण मिश्रण रखते हुए बीएसटी की संरचना करनी चाहिए और उसे उपलब्ध करना चाहिए। तथापि, यदि किसी विशेष विषय-वस्तु के पर्याप्त मात्रा में चैनल उपलब्ध नहीं हैं, तो उस प्रचालक द्वारा उन्हें अन्य विषय-वस्तुओं के चैनलों को शामिल करके संपूरित किया जा सकता है। यह भी उपबंध किया गया है कि प्रचालक को बीएसटी के 100 चैनलों के भीतर जन प्रसारक, प्रसार भारती के डीडी-भारती, डीडी-मलयालम, डीडी-पोथिगई, डीडी-ओडिया, डीडी-बांग्ला, डीडी-सप्तगिरि, डीडी-चंदना, डीडी-सहयाद्रि, डीडी-गिरनार, डीडी-कशीर, डीडी-एनई, डीडी-पंजाबी नामक चैनलों की पेशकश करनी होगी। इससे अपने गृह नगरों से दूर रहने वाले/अन्य स्थानों पर कार्यरत उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

11. इस विषय पर कि क्या बीएसटी का मूल्य-निर्धारण और आकार विभिन्न राज्यों, शहरों अथवा कस्बों के लिए अलग-अलग होना चाहिए, हालांकि कुछ हितधारकों ने कहा है कि इसे विभिन्न स्थानों के लिए अलग होना चाहिए, परंतु अधिकांश ने कहा कि बीएसटी की दर को और आकार को समूचे देश में समान रखा जाना चाहिए। प्राधिकरण की मान्यता है कि उपभोक्ताओं की अलग-अलग सामर्थ्य और उनकी पसंद के एक नगर के इलाकों में भी, और यहां तक कि एक ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जा रही सेवा वाले एक इलाके में भी सामर्थ्य व पसंद में भिन्नता के कारण, गणना करना संभव नहीं होगा। अन्य शब्दों में, व्यापक स्तर पर, एक समरूप प्रस्ताव, उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए बेहतर होता है, जिसे आसानी से संप्रेषित एवं लागू किया जा सकता है। बड़ी संख्या में हितधारकों के सुझावों के अनुरूप प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि बीएसटी का आकार और दर समूचे देश में समान रखा जाए।

2. संशोधित केबल टीवी अधिनियम उपबंध करता है कि बीएसटी में प्रदान किए जाने वाले एफटीए चैनल भी प्रचालक द्वारा भादूविप्रा द्वारा नियत किए गए टैरिफ पर अ-ला-कार्ट रूप में प्रदान किए जाने

चाहिए। बीएसटी का भाग बनने वाले चैनलों के अ-ला-कार्ट चैनल मूल्यों पर हितधारकों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। कुछ हितधारकों, जिनमें प्रसारक, एमएसओ और डीटीएच प्रचालक, कुछ वैयक्तिक उपभोक्ता, एक उपभोक्ता संगठन, अधिकांश एलसीओ तथा एक केबल प्रचालक संगठन शामिल हैं, ने यह कहा है कि इसे तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता, बड़ी संख्या में उपलब्ध चैनलों में से पसंद करने की उपभोक्ता की असुविधा तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किए गए अध्ययनों में निकले निष्कर्षों के आधार पर अधिदेशित नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, अनेक हितधारकों ने अ-ला-कार्ट रूप में चैनलों के प्रावधान का समर्थन किया तथा सुझाव दिया कि संयोजन के आधार पर अ-ला-कार्ट चैनल दरों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिसमें बीएसटी में औसत चैनल मूल्य के साथ संयोजन होगी (सामान्य बीएसटी चैनल की दर से 0-10 प्रतिशत अधिक औसत अ-ला-कार्ट दर के साथ) अथवा नियत दरें 1.5 रु0 से 5 रु0 के बीच होंगी, जिसमें अधिकांश 2 रु0 से 3 रु0 प्रति चैनल प्रति सब्सक्राइबर प्रतिमाह के बीच आती हैं।

13. प्रौद्योगिकी उपभोक्ताओं को चैनलों को चुनने का अवसर उपलब्ध कराती है तथा एड्रेसेबल डिजिटलीकरण का लाभ उठाने के लिए, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि उपभोक्ता, प्रचालक द्वारा पेश किए गए चैनलों में से न्यूनतम 100 फ्री-टु-एयर चैनलों की बीएसटी के लिए विकल्प दे सकता है अथवा बीएसटी के प्रभारों पर ऑपरेटर द्वारा अपने नेटवर्क पर संचारित किए जा रहे फ्री-टु-एयर चैनलों में से अपनी पसंद के 100 चैनल चुन सकता है। उपभोक्ता को यह विकल्प प्राप्त है कि वह किसी फ्री-टु-एयर चैनल अथवा बीएसटी में से किसी को भी न चुने।

बी. खुदरा टैरिफ

14. खुदरा टैरिफ के मुददे पर, अधिकांश हितधारकों की राय मुख्य रूप से तीन प्रस्तावों के इर्द-गिर्द घूमती है – (एक) खुदरा टैरिफ कैस मॉडल पर आधारित होना चाहिए; (दो) खुदरा टैरिफ को थोक स्तर पर विनिर्दिष्ट सीलिंगों के साथ जोड़ा जाए; तथा (तीन) खुदरा टैरिफ को स्थगनाधीन रखा जाए।

15. उन हितधारकों, जिन्होंने अधिसूचित कैस-क्षेत्रों में लागू टैरिफ मॉडलों को अपनाने का सुझाव दिया है, का मत है कि यह प्रणाली पिछले 5 से अधिक वर्षों से अच्छा कार्य कर रही है तथा इसके संबंध में सेवा प्रदाताओं की ओर से शून्य/न्यूनतम मुकदमेबाजी हुई है और उपभोक्ता भी टैरिफ के इस मॉडल से संतुष्ट हैं। इनमें से कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया है कि एचडी और विशिष्ट चैनलों के लिए इस

मॉडल में उपयुक्त उपबंध जोड़े जाने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एचडी चैनलों की पेशकश 5.35 रु0 की चैनल दर सीलिंग से लगभग 15 प्रतिशत अधिक पर की जानी चाहिए तथा विशिष्ट चैनलों को स्थगनाधीन रखा जाना चाहिए।

16. कुछ हितधारकों का यह मत है कि जब थोक दरों को विनियमित किया जा रहा है, तो खुदरा दरों को भी विनियमित किया जाना चाहिए तथा एड्रेसेबल प्लेटफार्म के प्रचालक को प्रसारकों द्वारा थोक पर उपलब्ध कराई जाने वाली चैनल की दरों तथा प्रचालकों द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली खुदरा दरों के बीच एक संयोजन हो सकता है। आदर्श रूप में, इस संयोजन का अवधारण उपगत कैरिज लागत में लाभ मार्जिन को जोड़कर किया जाना चाहिए तथा तदनुसार, विभिन्न हितधारकों द्वारा खुदरा चैनल दरें चैनल की थोक दर से ऊपर 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच विनिर्दिष्ट की गई हैं। कुछ हितधारकों ने चैनल दरों की परिधि पे-चैनलों के लिए 6 रु0 से 7 रु0 के बीच तथा एफटीए चैनलों के लिए 2 रु0 से 3 रु0 के आस-पास भी विनिर्दिष्ट की है, जिन्हें उन्होंने सभी विषय-वस्तुओं के लिए समान रखना बताया गया है जबकि अन्य कुछ हितधारकों ने पे और एफटीए चैनलों, दोनों के लिए भिन्न सीलिंगों का सुझाव दिया है, जो विभिन्न विषय-वस्तुओं के चैनलों के लिए 3 रु0 से 10 रु0 के बीच है।
17. जिन हितधारकों ने खुदरा स्तर पर स्थगन की हिमायत की है, उन्होंने कहा है कि खुदरा स्तर पर स्थगन ने डीटीएच क्षेत्र में भली प्रकार से कार्य किया है तथा अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में डीटीएच के सेवा-मार्ग में वृद्धि का उल्लेख किया है। इन हितधारकों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि डीटीएच और आईपीटीवी के साथ प्रतिस्पर्धी प्लेटफार्म होने के नाते डीएएस में समान टैरिफ प्रणाली विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए ताकि विभिन्न एड्रेसेबल टीवी प्लेटफार्मों के बीच समान प्रतिस्पर्धा निर्दिष्ट किया जा सके।
18. एड्रेसेबिलिटी, उपभोक्ता के लिए अ-ला-कार्ट विकल्प और अन्य एड्रेसेबल प्लेटफार्मों से पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की उपलब्धता, खुदरा मूल्य-निर्धारण के स्थगन पर पर्याप्त जांचोपाय उपलब्ध कराते हैं जबकि ऐकेजिंग और मूल्य-निर्धारण का अवधारण प्रचालकों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, डीएएस क्षेत्रों के लिए खुदरा स्तर पर स्थगन विभिन्न एड्रेसेबल टीवी प्लेटफार्मों के मध्य समान प्रतिस्पर्धा बनाए रखेगा। तदनुसार, प्राधिकरण ने डीएएस क्षेत्रों के लिए भी, खुदरा स्तर की टैरिफ पर स्थगन को बनाए रखने का निर्णय लिया है। तथापि, एफटीए चैनलों के मामले में, चूंकि प्रसारक को ऑपरेटर द्वारा कोई

शुल्क नहीं देता होता है, अतः प्राधिकरण का अभिमत है कि ऑपरेटर द्वारा अपने डिजिटल नेटवर्क प्रणाली पर संचारित सभी एफटीए चैनलों, जिनके लिए वह स्वयं खुदरा स्तर पर चैनल का मूल्य निर्धारण करता है, एक समान मूल्य निर्धारण होना चाहिए।

सी. चैनलों का अ—ला—कार्ट प्रावधान

19. जहां तक उपभोक्ता का संबंध है, एड्रेसेबल टीवी प्रणाली द्वारा उपभोक्ता को जो मुख्य लाभ प्रदान किया जाता है, वह उसे उसकी पसंद के चैनलों को चुनने में समर्थ बनाना है। 21 जुलाई 2010 के टैरिफ आदेश में, प्रचालकों को उनके नेटवर्क पर संचारित किए गए सभी पे—चैनलों की अ—ला—कार्ट आधार पर पेशकश करने के लिए अधिदेशित किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति प्रदान किए गए सभी चैनलों में से लगभग 75 प्रतिशत चैनल एफटीए चैनल हैं। इस प्रकार, अ—ला—कार्ट आधार पर केवल पे—चैनल उपलब्ध कराना मुख्य रूप से सब्सक्राइबरों को चैनलों की उनकी पसंद का प्रयोग करने से वंचित करेगा। अतः प्राधिकरण ने किसी प्रचालक नेटवर्क पर संचारित किए गए एफटीए और पे—चैनलों, दोनों को कवर करने के लिए चैनलों के अ—ला—कार्ट प्रावधान को विस्तारित करना उपयुक्त समझा क्योंकि यह तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है और एक ओर प्रचालक पर प्रणालीगत रूप से अधिक बोझ नहीं डालता है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को टीवी सेवाओं के वितरण क्षेत्र की एड्रेसेबिलिटी के साथ डिजिटलीकरण से लाभान्वित होने में भी सबल बनाता है। तथापि, चैनलों के बंडल्ड पैकेजों के लाभ भी सब्सक्राइबरों को प्राप्त होने चाहिए। सब्सक्राइबर अ—ला—कार्ट चैनलों या बुकेसमूहों/पैकेजों या दोनों के संयोजन के बीच चुनाव करने में समर्थ होने चाहिए। इससे एड्रेसेबल प्रणालियों पर अ—ला—कार्ट पेशकशों के साथ बुकें/पैकेजों का सह—अस्तित्व सुनिश्चित होगा। तदनुसार, सब्सक्राइबरों को बुकेसमूहों/पैकेजों का प्रावधान भी टैरिफ आदेश का एक भाग है।
20. सब्सक्राइबर को चैनलों की अ—ला—कार्ट पसंद का अधिदेश देते हुए, प्राधिकरण—इस तथ्य को भी ध्यान में रखता है कि यदि सब्सक्राइबरों द्वारा दिए जाने वाले विकल्पों में बार—बार परिवर्तन किए जाएंगे, तो सेवा प्रदाताओं को तकनीकी और प्रचालन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सब्सक्राइबरों द्वारा दिए गए विकल्पों के संबंध में कार्रवाई करने में सेवा प्रदाताओं को रथायित्व प्रदान करने का उपाय उपलब्ध कराने हेतु, उस प्रावधान, जिसमें सेवा प्रदाता, उपभोक्ता की पसंद के अ—ला—कार्ट चैनलों को एक न्यूनतम प्रतिबद्धता अवधि तक बनाए रखने की शर्त निर्धारित कर सकता है, को बनाए रखा गया है।

डी. खुदरा स्तर पर युग्म-शर्ते

21. भादूविप्रा ने कैस और गैर-कैस क्षेत्रों में वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए अपने 21 नवम्बर 2006 के टैरिफ आदेश में एक प्रावधान किया जिसमें किसी चैनल की अ-ला-कार्ट दर तथा बुके की दर, जिसमें यह चैनल एक भाग बनता है, के बीच संबंध स्थापित करने के लिए युग्म-शर्त परिभाषित की गई थीं। ये शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिए आरंभ की गई थी कि कहीं-उपभोक्ता को बुके(समूह) के लिए सब्सक्राइब करने के लिए बाध्य न किया जाए और ऐसा न हो कि उसके लिए पसंद करने के लिए कोई विकल्प शेष ही न रह जाए। ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि वैयक्तिक चैनल की पसंद भ्रामक न हो। ये शर्तें चैनल मूल्यों में वृद्धि तथा पसंद को भ्रामक बनाने के लिए बुके के मूल्य-निर्धारण पर एक नियंत्रक के रूप में कार्य करती हैं।
22. दिनांक 21 जुलाई, 2010 के टैरिफ आदेश में अ-ला-कार्ट का प्रावधान करते समय, प्राधिकरण ने हल्का नियंत्रण रखने एवं अ-ला-कार्ट चैनलों के मूल्य निर्धारण पर कोई शर्त अधिदेशित नहीं करने का निर्णय लिया था। व्याख्यात्मक ज्ञापन में कहा गया था कि तथापि, प्राधिकरण, बाजार पर कड़ी नजर रखेगा तथा सार्वजनिक हित में जब भी आवश्यक होगा, हस्तक्षेप कर सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में जहां डीटीएच सैक्टर के ऑपरेटरों को पैकेज और कीमत की पेशकश करने की अनुमति दी गई है, में यह देखा गया है कि अ-ला-कार्ट चैनलों के सब्सक्रिप्शन में वृद्धि (अप-टेक) नगण्य है। अ-ला-कार्ट चैनलों के अपटेक में कम वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है कि अ-ला-कार्ट चैनलों की दरें, बुके दरों की तुलना में, विशेषतः प्रवेश स्तर पैक से बेमोलैरूप से अधिक हैं।
23. इसके अतिरिक्त, दोनों, प्रवेश स्तर पर एवं अन्य छोटे अतिरिक्त पैकों, में लोकप्रिय चैनल वितरित किए जा रहे हैं। नतीजतन, उपभोक्ता, अपनी मांग को पूरा करने हेतु अक्सर अतिरिक्त पैक लेने के लिए बाध्य होता है और अंततः अधिक राशि का भुगतान कर रहा है। इस प्रकार, एड्रेसेबिलिटी का मुख्य उददेश्य विफल हो गया है एवं गैर-एड्रेसेबिलिटी की कमियां जारी हैं। अ-ला-कार्ट प्रस्ताव के माध्यम से उपभोक्ताओं हेतु विकल्प सुनिश्चित करने एवं अ-ला-कार्ट मूल्य के विषम निर्धारण को रोकने के लिए खुदरा स्तर पर भी मूल्य निर्धारण करने के लिए दोहरी शर्तों को लागू कर दिया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि खुदरा स्तर पर दोहरी शर्त, अ-ला-कार्ट चैनलों की कीमतों की तुलना में(रु-बरु) बुके चैनलों कीमतों को चयन करने के लिए उपभोक्ता को उसके विकल्पों का प्रभावी

रूप से चयन करने की अनुमति प्रदान करेगा। इन दोहरी शर्तों के अनुपालन हेतु डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के विद्यमान ऑपरेटरों के लिए 60 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है।

ई. न्यूनतम मासिक अभिदान शुल्क

24. वितरकों के प्रचालनों की व्यवहार्यता और स्थायित्व को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। दिनांक 21 जुलाई, 2010 के टैरिफ आदेश में, एक प्रावधान विद्यमान है जो कि ऑपरेटरों को ऐसे सेवा प्रदाताओं की सेवाओं का उपयोग करने के लिए एक न्यूनतम मासिक सब्सक्रिप्शन निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। एक प्रकार से, प्रवेश स्तर के विकल्प, उन न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्रभारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी ऑपरेटरों द्वारा सब्सक्राइबरों से सेवाएं प्रदान करने की लागत के रूप में संग्रहित करने की अपेक्षा होती है।

25. परामर्श प्रक्रिया के दौरान उद्योग के हितधारकों ने इस बात पर बल दिया कि केबल क्षेत्र में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या अत्यधिक है जिनके पास सीमित भुगतान क्षमता है। ऐसे सब्सक्राइबरों के लिए प्राधिकरण का मत है कि 150 रु0 (अधिकतम) का न्यूनतम मासिक सब्सक्रिप्शन प्रभार एक सम्भावित प्रवेश व्यवधान होगा। अतः प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि एकल न्यूनतम मासिक सब्सक्रिप्शन विकल्प के रूप पर डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली के सेवा प्रदाता को कम-से-कम दो न्यूनतम मासिक सब्सक्रिप्शन शुल्क के विकल्प निर्दिष्ट करने चाहिए। एक विकल्प वह होगा जहां प्रचालक एक न्यूनतम सब्सक्रिप्शन निर्दिष्ट कर सकता है, जो 100 रु0 प्रति सब्सक्राइबर प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा तथा दूसरा वह जिसमें प्रचालक इस राशि को निर्दिष्ट कर सकता है, जो 150 रु0 प्रति सब्सक्राइबर प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी। पहले न्यूनतम मासिक सब्सक्रिप्शन के विकल्प (100 रु0 प्रति माह से अधिक नहीं) में उपभोक्ता एमएसओ के नेटवर्क पर संचारित किए गए एफटीए चैनलों में से अ-ला-कार्ट आधार पर कोई भी 100 चैनल या बीएसटी ले सकता है। यदि सब्सक्राइबर बीएसटी या अन्य एफटीए चैनलों के साथ या उसके बिना, एक या अधिक पे-चैनलों का विकल्प लेता है, प्रचालक उसे द्वितीय मासिक सब्सक्रिप्शन प्रभार विकल्प (150 रु0 प्रति माह से अधिक नहीं) के अनुसार प्रभारित कर सकता है। जहां तक अन्य एड्रेसेबल प्लोटफार्म का संबंध है, वहां विद्यमान न्यूनतम मासिक सब्सक्रिप्शन विकल्प को बनाए रखा गया है।

एफ. पैकेज / मूल्य-निर्धारण की संरचना में परिवर्तन से संबंधित उपबंध

26. उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए, दिनांक 21.07.2010 के टैरिफ आदेश में एक उपबंध बनाया गया है कि प्रचालक उसके द्वारा पेश किए गए किसी सब्सक्रिप्शन पैकेज के लिए उक्त सब्सक्रिप्शन पैकेज में नामांकन की तारीख से न्यूनतम छह माह की अवधि के लिए प्रभारों में वृद्धि नहीं करेगा। तथापि, प्रचालकों ने अनुरोध किया है कि इस उपबंध में संशोधन किया जाए ताकि यदि पैकेज का भाग बनने वाले एक या अधिक एफटीए चैनलों के पे-चैनलों में बदलने की स्थिति में इस उपबंध का अनुपात ऐसे चैनलों को उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क संचारित करने के रूप में प्रचालकों पर अनावश्यक बोझ न बने। तदनुसार, प्रचालकों द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, संबंधित खण्ड में एक परतुक जोड़ा गया है जो प्रचालकों को या तो पैकेज से विशेष चैनल हटाने या उपभोक्ता के विवेक के आधार पर तदनुसार प्रभारों को संशोधित करने की अनुमति प्रदान करता है।

जे. आय हिस्सा

27. अधिकांश प्रसारकों/मूल्यांककों ने सुझाव दिया कि डिजिटल एड्रेसेबल केबल प्रणाली के ऑपरेटरों के बीच आय का हिस्सा भादूविप्रा द्वारा विनियमित किए जाने के स्थान पर पारस्पर बातचीत पर निर्धारित होना चाहिए। उनमें से कुछ ने सुझाव दिया कि बीएसटी का राजस्व हिस्सा भादूविप्रा द्वारा विनियमित होना चाहिए जबकि शेष भाग पारस्परिक बातचीत पर आधारित होना चाहिए। यदि राजस्व हिस्सा भादूविप्रा द्वारा परिभाषित किया जाता है, तो यह बीएसटी तथा अन्य आय के लिए समान होना चाहिए। कुछ प्रसारकों ने एलसीओ के लिए अधिकतम 15–20 प्रतिशत भाग का सुझाव दिया तथा एक ने सुझाव दिया कि राजस्व की हिस्सेदारी एमएसओ और एलसीओ के लिए क्रमशः 55:45 के अनुपात में होनी चाहिए। अधिकांश उद्योग संघों ने भी इस बात का समर्थन किया कि राजस्व हिस्सा पारस्परिक बातचीत पर आधारित होना चाहिए।

28. एमएसओ और एलसीओ के बीच सब्सक्रिप्शन राजस्व के हिस्से के निर्धारण के मुददे पर मल्टी सिरटम ऑपरेटरों के बीच मतभेद है। कुछ ने सुझाव दिया कि यह पारस्परिक बातचीत पर आधारित होना चाहिए जबकि अन्य ने सुझाव दिया है कि इसे भादूविप्रा द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि राजस्व हिस्सा कैस मॉडल की ही भाँति हो सकता है जिसमें डीएस क्षेत्रों में एमएसओ द्वारा किए जाने वाले निवेश को ध्यान में रखते हुए एमएसओ के लिए उच्च राजस्व भाग निर्धारित होगा। लगभग सभी एलसीओ भादूविप्रा द्वारा सब्सक्रिप्शन राजस्व के विनियमन के पक्ष में थे।

उनमें से कुछ ने सुझाव दिया कि वर्तमान कैस प्रणाली का अनुपालन डीएस के लिए भी किया जाना चाहिए। एलसीओ द्वारा बीएसटी के लिए (एलसीओ के पक्ष में 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच) तथा शेष आय (एलसीओ के पक्ष में 25–60 प्रतिशत के बीच) के लिए विभिन्न अनुपातों का सुझाव दिया गया।

29. भादूविप्रा ने अपने 21 जुलाई 2010 के टैरिफ आदेश में यह विनिर्दिष्ट किया था कि एमएसओ और एलसीओ के बीच राजस्व हिस्से का निर्णय पारस्परिक बातचीत से किया जाना चाहिए। परामर्श प्रक्रिया के दौरान तथा विभिन्न उद्योग मंचों पर, इस बात पर जोर दिया गया है कि विशाल केबल समुदाय के समान प्रतिस्पर्धात्मकता और उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से राजस्व हिस्से को परिभाषित करना चाहिए। यह भी कहा गया है कि बुनियादी सेवा टियर के लिए राजस्व हिस्से में राशि को एमएलओ और एमएसओ के बीच स्पष्टतः संविभाजित किया जाना चाहिए।
30. प्रत्येक डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के उपभोक्ता प्रबंधन सिस्टम (एसएमएस) में अभिदाताओं के आधार (बेस) और इसके प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा अभिदान किए गए चैनलों/बुके/पैकेजों से संबंधित डाटा बेस है। यह डाटा बेस सत्यापनीय और अंकेक्षणीय है। साथ ही एमएसओ को यह आदेश है कि सभी चैनलों की अलग-अलग अ-ला-कार्ट दर तथा बुके/पैक, यदि कोई उसके द्वारा पेश किए जा रहे हों तो उनकी दरों को घोषित करें। इन विवरणों के साथ, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ जुड़े हुए स्थानीय केबल ऑपरेटर को वास्तविक अभिदत्त आय की जानकारी होती है। डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम में अंतर्निहित पारदर्शिता के आलोक में प्राधिकरण का अभिमत है कि, यूंकि इस पर मोल-तोल करने के पैरामेगा अब विवाद रहित हैं, अतः यह उचित होगा कि, एमएसओ व एलसीओ परस्पर मोल-तोल के आधार पर अभिदत्त (सब्सक्राइब्ड) आय की साझेदारी करें। यदि वे आय साझेदारी के परस्पर सम्मत समझौते पर पहुंचने में असफल रहते हैं तो टैरिफ आदेश के भाग-IV में निर्धारित अनुसार वे अभिदत्त आय में हिस्सेदारी करेंगे।
31. बड़ी संख्या में हितधारकों द्वारा अधिसूचित कैस क्षेत्रों के आय हिस्सेदारी मॉडल को अपनाने का पक्ष लिया गया है। अधिसूचित कैस क्षेत्रों में पे चैनलों के लिए अभिदत्त आय को प्रसारक, एमएसओ और एलसीओ के बीच क्रमशः 45:30:25 के अनुपात में बांटा जाता है। कैस मॉडल के आधार पर आय बंटवारा तंत्र पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है। यद्यपि, आय बंटवारे का यह सूत्र सीधे डीएस क्षेत्रों, जहां प्रसारक के बजाए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा चैनल/बुके का खुदरा मूल्य निर्धारित किया

जाता है, पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता है, इससे कुछ उपयोगी सूत्र निकाला जा सकता है। डिजिटल एड्सेबल केबल टीवी सिस्टम में एफटीए चैनलों (साथ ही साथ पे चैनलों) को मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा समाहित किया जाना और डिजिटल और कूट (एनक्रिटेड) रूप में ले जाया जाना है। इन्हें मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की एसएमएस प्रणाली के माध्यम से विधिवत् हिसाब में लिया व प्राधिकृत किया जाता है तथा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर के नेटवर्क पर संचारित किया जाता है। यह अधिसूचित कैस क्षेत्रों में पे चैनलों के प्रबंधन (कैरिज) के सदृश्य है। अतः जहां तक एफटीए चैनलों/बुके के लिए आय की हिस्सेदारी का संबंध है, कैस सूत्रों को अपनाया जा सकता है। चूंकि एफटीए चैनल होने के कारण, प्रसारक को इसके चैनलों के लिए भुगतान नहीं किया जाना है, अतः आय की भागीदारी, एमएसओ और एलसीओ के बीच क्रमशः 55:45 के अनुपात में आती है।

32. जहां तक पे चैनलों तथा पे चैनलों वाले बुके का प्रश्न है, इनमें मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से यह अपेक्षित है कि वह अपनी अभिदान की आय में से प्रसारक को भुगतान करे। इसमें यह अपेक्षित है कि उनकी आय का हिस्सा बीएसटी/एफटीए के लिए निर्धारित (अ-ला-कार्ट अथवा बुके) 55 प्रतिशत के हिस्से की तुलना में अधिक होना चाहिए। अधिसूचित कैस क्षेत्रों में, स्थानीय केबल ऑपरेटर के लिए पे चैनलों के लिए 25 प्रतिशत आय की हिस्सेदारी को, इस आधार के मद्दे नजर निर्धारित किया गया था कि, बीएसटी से होने वाली कुल अभिदान आय, एलसीओ द्वारा रखी जाएगी। डिजिटल एड्सेबल केबल टीवी सिस्टम में बीएसटी और एफटीए चैनलों (अ-ला-कार्ट अथवा बुके) से होने वाली अभिदान आय को मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ (एमएसओ:एलसीओ) 55:45 के अनुपात में बांटी जाएगी। अतः एक तर्क यह हो सकता है कि स्थानीय केबल ऑपरेटर को अपने कारोबार को कायम रखने के लिए पे चैनलों और पे चैनलों वाले बुके(समूहों) में से अधिक आय मिलनी चाहिए। इस संबंध में, कैस और डीएस के बीच मुख्य अंतर यह है कि कैस में फ्री-टु-एयर चैनलों को स्थानीय केबल ऑपरेटर द्वारा डाउनलिंक और वितरित किया जाता था जबकि डीएस में फ्री-टु-एयर चैनलों सहित सभी चैनलों को मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा डाउनलिंक, एनक्रिप्ट और वितरित किया जाता है। यदि बुके(समूह) में पे व एफटीए दोनों चैनल हैं तो पे व एफटीए चैनलों की आय के घटकों को विभक्त करना कठिन होगा, अतः ऐसे बुके(समूहों) से होने वाली आय को पे चैनलों के लिए निर्धारित अनुपात में बांटना विवेकपूर्ण होगा। इसके अलावा, अ-ला-कार्ट आधार पर पे चैनलों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटर को प्रोत्साहित करने के लिए, स्थानीय केबल ऑपरेटर के लिए आय में बेहतर हिस्सेदारी पर विचार किया गया है जो अंततः उपभोक्ता के लिए बेहतर विकल्प सुनिश्चित करेगा। अतः पे चैनलों

अथवा पे चैनलों वाले बुके(समूहों) पर स्थानीय केबल ऑपरेटर के लिए आय में से 25 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी प्राप्त करने का प्रकरण बनता है। केवल एफटीए अभिदान(अ—ला—कार्ट, बुके अथवा बीएसटी) के लिए यह वर्तमान में 45 प्रतिशत है। अतः पे चैनलों या पे चैनलों सहित बुके(समूह) पर स्थानीय केबल ऑपरेटरों के लिए बीच का रास्ता अपनाने अर्थात् 35 प्रतिशत से यह अपेक्षा की जाती है कि इससे स्थानीय केबल ऑपरेटर के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न होगी। इससे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के लिए अभिदान आय का 65 प्रतिशत बचा रहेगा। अभिदान आय के अलावा, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के पास कैरिज फीस के रूप में आय के अन्य स्रोत भी हैं। साथ ही डीएस प्रणाली में रिटेल पैकेजिंग और मूल्य निर्धारण भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा किया जाएगा। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पे चैनलों और एफटीए चैनलों सहित अथवा रहित पे चैनलों वाले बुके(समूहों) से संबंधित अभिदान आय को मल्टी सिस्टम ऑपरेटर व स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच 65:35 के अनुपात में सहभाजित किया जाएगा।

एच. विज्ञापन—मुक्त चैनल

33. विज्ञापन—मुक्त चैनलों की अर्थक्षमता के मुद्दे पर अनेक हितधारकों का विचार था कि विज्ञापन—मुक्त चैनल अर्थक्षम हैं, जबकि हितधारकों की एक बड़ी संख्या, जिसमें उपभोक्ताओं सहित हितधारकों के सभी वर्ग शामिल थे, का विचार था कि भारतीय बाजार में विज्ञापन—मुक्त चैनलों की अर्थक्षमता के निर्धारण का निर्णय बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
34. विज्ञापन—मुक्त चैनलों के लिए टैरिफ संवितरण के मामले पर, अधिकांश हितधारकों ने डीएस क्षेत्रों में थोक और खुदरा, दोनों ही स्तरों पर स्थगन की हिमायत की। तथापि, कुछ एमएसओं ने सुझाव दिया है कि खुदरा की स्थगनाधीन रखते हुए थोक टैरिफ को विनियमित किया जाना चाहिए जबकि एक केबल प्रचालक संघ ने सुझाव दिया कि विज्ञापन—मुक्त चैनलों के लिए टैरिफ भादूविप्रा द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए।
35. जहाँ तक विज्ञापन—मुक्त चैनलों के लिए सब्सक्रिप्शन राजस्व की साझेदारी का संबंध है, सभी प्रसारकों की यह राय थी कि इसे सेवा प्रदाताओं के बीच वाणिज्यिक बातचीत पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अन्य हितधारकों में इस मुद्दे पर मतभेद था। इनमें से कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि राजस्व हिस्से पर उसी प्रकार से निर्णय लिया जाना चाहिए जैसे अन्य पे—चैनलों के मामले में किया जाता है जबकि अन्य हितधारकों, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों और स्थानीय केबल ऑपरेटरों के लिए भिन्न प्रतिशतों का सुझाव दिया, हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया।

36. विज्ञापन-मुक्त फार्मेट में (विज्ञापन-मुक्त चैनल) चैनल प्रदान करना भारतीय टेलीविजन बाजार में एक नवीन प्रक्रिया है। ये चैनल मांग के आधार पर चलाए जाते हैं तथा सामान्यतः दर्शकों के लक्षित समूह को ही सेवा प्रदान करते हैं। चूंकि विज्ञापन-मुक्त चैनल पूर्णतः सञ्चारिकरण राजस्व पर निर्भर होते हैं तथा मांग पर आधारित होते हैं, हितधारकों की बड़ी संख्या की भावना के अनुसार प्राधिकरण ने विज्ञापन-मुक्त चैनलों को पूर्णतः स्थगनाधीन रखने का निर्णय लिया। प्रधान चैनल अर्थात् एचडीटीवी चैनल और 3डी चैनल, जिनके लिए विशेष एसटीबी की आवश्यकता होती है, पहले से ही स्थगनाधीन हैं तथा वे स्थगनाधीन बने रहेंगे। प्राधिकरण उपयुक्त समय पर स्थिति की समीक्षा करेगा। जहां तक राजस्व भाग का संबंध है, इसे एमएसओ और एलसीओ के बीच उसी अनुपात में बांटा जाएगा, जैसाकि अन्य चैनलों के लिए परिभाषित है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2012

No. 1-9/2012 B & CS.— In exercise of the powers conferred by sub-clauses (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No.39 ,----

- (a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government by proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 and clause (d) of sub-section (1) of section 11 of the said Act, and
- (b) published under notification No. S.O. 44 (E) and 45 (E) dated 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,----

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 (1 of 2010) , namely:-

THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES (FOURTH) (ADDRESSABLE SYSTEMS) TARIFF (FIRST AMENDMENT) ORDER, 2012

1. (1) This Order may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff (First Amendment) Order, 2012 (3 of 2012).
(2) This Order shall come into force from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

2. Clause 2 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 (1 of 2010) (hereinafter referred to as the principal Tariff Order) shall be substituted, namely:—

“Applicability.”—This Order shall be applicable to broadcasting services and cable services provided to subscribers, through digital addressable systems, throughout the territory of India.”

3. In clause 3 of the principal Tariff Order,—

- (a) for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(b) “addressable system” means an electronic device (which includes hardware and its associated software) or more than one electronic device put in an integrated system through which signals of digital addressable system can be sent in encrypted form, which can be decoded by the device or devices, having an activated Conditional Access System at the premises of the subscriber within the limits of authorisation made, through the Conditional Access System and the subscriber management system, on the explicit choice and request of such subscriber, by multi-system operator or DTH operator or IPTV operator or HITS operator to the subscriber;”

- (b) after sub-clause (e), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

“(ea) “basic service tier” means a package of free-to-air channels to be offered, with an option to subscribe, by a cable operator for a single price to subscribers of the area in which his cable television network is providing service;”

(c) for sub-clause (m), the following sub-clause shall be substituted, namely:---

“(m) “Cable Operator” means any person who provides cable service through a cable television network or otherwise controls or is responsible for the management and operation of a cable television network and fulfils the prescribed eligibility criteria and conditions;”

(d) after sub-clause (s), the following sub-clause shall be inserted, namely:---

“(sa) “encrypted”, in respect of a signal of cable television network, means the changing of such signal in a systematic way so that the signal would be unintelligible without use of an addressable system and the expression “unencrypted” shall be construed accordingly;”

(e) for sub-clause (x), the following sub-clause shall be substituted, namely:---

“(x) “Multi-System Operator” means a cable operator who has been granted registration under rule 11 of the Cable Television Networks Rules, 1994, as amended by rule 8 of the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2012, and who receives a programming service from a broadcaster or its authorised agencies and re-transmits the same or transmits his own programming service for simultaneous reception either by multiple subscribers directly or through one or more local cable operators and includes his authorised distribution agencies, by whatever name called;”

(f) for sub-clause (za), the following sub-clause shall be substituted, namely:---

“(za) “pay channel”, in respect of a digital addressable system, means a channel for which subscription fees is to be paid to the broadcaster by multi-system operator or DTH operator or IPTV operator or HITS operator and due authorisation needs to be taken from the broadcaster for its re-transmission on the digital addressable system;”

(g) for sub-clause (zb), the following sub-clause shall be substituted, namely:---

“(zb) “programme” means any television broadcast and includes

(i) exhibition of films, features, dramas, advertisements and serials;

(ii) any audio or visual or audio-visual live performance or presentation; and the expression "programming service" shall be construed accordingly;"

(h) in sub-clause (zd), the word "pay" shall be omitted.

(i) for sub-clause (ze), the following sub-clause shall be substituted, namely:—
“(ze) “subscriber” means any individual, or association of individuals, or a company, or any other organization or body who receives the signals of multi-system operator or DTH operator or IPTV operator or HITS operator at a place indicated by him or it to multi-system operator or DTH operator or IPTV operator or HITS operator, without further transmitting it to any other person and includes ordinary subscribers and commercial subscribers unless specifically excluded;”

(j) after sub-clause (ze), the following sub-clause shall be inserted, namely:—
“(zea) “subscriber management system” means a system or device which stores the subscriber records and details with respect to name, address and other information regarding the hardware being utilised by the subscriber, channels or bouquets of channels subscribed to by the subscriber, price of such channels or bouquets of channels as defined in the system, the activation or deactivation dates and time for any channel or bouquets of channels, a log of all actions performed on a subscriber’s record, invoices raised on each subscriber and the amounts paid or discount allowed to the subscriber for each billing period;”

4. In clause 5 of the principal Tariff Order, the following proviso shall be inserted, namely:—
“*Provided that* in case the multi-system operator and the local cable operator fail to arrive at mutual agreement, the charges collected from the subscribers shall be shared in the following manner:-

(a) the charges collected from the subscription of channels of basic service tier, free to air channel and bouquet of free to air channels shall be shared in the ratio of 55:45 between multi-system operator and local cable operator respectively; and

(b) the charges collected from the subscription of channels or bouquet of channels or channels and bouquet of channels other than those specified under clause (a) shall be shared in the ratio of 65:35 between multi-system operator and local cable operator respectively.”

5. In clause 6 of the principal Tariff Order, for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(1) Every multi-system operator or DTH operator or IPTV operator or HITS operator providing broadcasting services or cable services to its subscribers using an addressable system shall, from the date of coming into force of this Order, offer or cause to offer all channels offered by it to its subscribers on a-la-carte basis and shall specify the maximum retail price for each channel, as payable by the ordinary subscriber:

Provided that the a-la-carte rate of free to air channels shall be uniform.”

6. In clause 6 of the principal Tariff Order,---

(a) in sub-clause (1), after the first proviso the following provisos shall be inserted, namely:—

“*Provided further that* in case a multi-system operator or DTH operator or IPTV operator or HITS operator providing broadcasting services or cable services to its subscribers, using a digital addressable system, offers channels as a part of a bouquet, the rate of such channels forming part of that bouquet shall be subject to the following conditions, namely:—

(a) the sum of the a-la-carte rates of the channels forming part of such a bouquet shall in no case exceed one and half times of the rate of that bouquet of which such channels are a part; and

(b) the a-la-carte rate of each channel forming part of such a bouquet shall in no case exceed three times the average rate of channel of that bouquet of which such channel is a part;

Provided also that every multi-system operator or DTH operator or IPTV operator or HITS operator, providing broadcasting services and cable services, through digital addressable systems, before the date of commencement of this Tariff Order and continues to provide such services after such commencement shall, within sixty days

from the date of such commencement, comply with the provisions of the second proviso.”

(b) after sub-clause (1), the following sub-clause shall be inserted, namely:----

“ (1A) Every multi-system operator providing cable services to the subscribers, using digital addressable cable TV system, directly or through its linked local cable operator, shall offer a package of a minimum of one hundred free to air channels as basic service tier including the channels of Prasar Bharati, namely DD-Bharati, DD-Malyalam, DD-Podhigai, DD-Odiya, DD-Bangla, DD-Saptagiri, DD-Chandana, DD-Sahyadri, DD-Girnar, DD-Kashir, DD-NE, DD-Punjabi.

(1B) It shall be open to the subscriber to choose any combination of free to air channels up to one hundred channels, in lieu of the basic service tier offered by the multi-system operator.

Provided that it shall be open to the multi-system operator to specify a minimum monthly subscription, not exceeding one hundred rupees (excluding taxes) per subscriber, towards the basic-service tier or the free to air channels chosen by the subscriber in lieu of the basic service tier.

(1C) The basic service tier offered by the multi-system operator shall include at least five channels of the each genre namely news and current affairs, infotainment, sports, kids, music, lifestyle, movies and general entertainment in Hindi, English and regional language of the concerned region.

Provided that in case sufficient number of free to air channels of a particular genre is not available, the multi-system operator shall include in the basic service tier the channels of the other genres.

(1D) It shall be open to the subscriber of the digital addressable cable TV to subscribe to basic service tier or basic service tier and one or more pay channel or only free to air channels or only pay channels or pay channels and free to air channels.

(1E) If a digital addressable cable TV subscriber subscribes to the pay channels, in a-la-carte or bouquet or a combination of a-la-carte and bouquet, with or without free to air channels, it shall be open to the multi-system operator to specify a minimum monthly subscription, not exceeding one hundred and fifty rupees (exclusive of taxes) per month.”

(c) after sub-clause (4), the following proviso shall be inserted, namely:----

“Provided that nothing contained in sub-clause (4) shall apply to the subscribers of the digital addressable cable TV systems.”

7. In clause 8 of the principal Tariff Order, in sub-clause (1), the following proviso shall be inserted, namely:---

“Provided that if a free to air channel, forming part of the subscription package, is converted into pay channel by the broadcaster, based on the verifiable consent of the subscriber, the multi-system operator or DTH operator or IPTV operator or HITS operator may either remove the said channel from the subscription package of such subscriber and reduce the price of the subscription package by an amount equal to the a-la-carte price of such free to air channel or may increase the price of the subscription package by an amount not exceeding the difference between the a-la-carte price of such free to air channel and the a-la-carte price of the said channel after its conversion into pay channel.”

8. In clause 9 of the principal Tariff Order, -----

“(a) in sub-clause (5), the word “pay” shall be omitted;

(b) in sub-clause (5), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:---

“Provided further that every such operator who commences its services after coming into force of this Tariff Order shall submit to the Authority such reports before commencement of its services and thereafter any changes in the rates shall be reported thirty days prior to the change:”

WASI AHMAD, Advisor

[ADVT. III/4/142/12/Exty.]

Note.----The Explanatory Memorandum annexed to this Order explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff (First Amendment) Order, 2012 (3 of 2012).

Annexure**Explanatory Memorandum****I. Background**

1. In the last few years, the exponential growth in the number of TV channels (both Free To Air and Pay) combined with the inherent limitations of the analog cable TV systems has posed several challenges in the cable TV sector, mainly due to capacity constraints and non-addressable nature of the network. With time and evolution of technology, new addressable TV platforms like DTH, IPTV etc. were introduced to the masses. The evolution of technology also paved way for bringing about digitization with addressability in the cable TV sector. Accordingly, after studying the subject at length and undertaking a public consultation process, the Authority, on 5th August 2010, gave its recommendations on implementation of Digital Addressable Cable TV Systems (DAS) across the country along with a roadmap to achieve the same.
2. The Government, on 25th October, 2011, issued an Ordinance amending the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, enabling the implementation of digital addressable cable TV systems in India. Thereafter, the Government also issued a notification dated 11th November, 2011, which laid down the roadmap for implementation, in a four phased manner, from June 2012 to December, 2014. The Ordinance dated 25th October, 2011, subsequently, in December, 2011, became an Act. The said amendment Act, apart from other provisions, provides for basic service tier (BST) to be offered by the operators of digital addressable cable TV systems, having its composition and tariff prescribed by TRAI.
3. Earlier, TRAI had, on 21st July 2010, issued the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010, applicable to broadcasting services and cable services provided to subscribers, through addressable systems, throughout the territory of India except cable services provided through cable television networks in the notified CAS areas. Considering the Cable Television Networks (Regulation) Amendment Act 2011, and the notification dated 11.11.2011 mentioned above, suitable amendments are required to be made in the tariff stipulations prescribed in the said tariff order. Therefore, the Authority initiated a consultation process on the issues relating to implementation of digital addressable cable TV

systems. The consultation issues include, apart from other issues related to interconnection and QoS, the issues related to the tariff and composition of Basic Service Tier (BST), retail tariff, tariff for advertisement free channels and revenue share between Multi-System Operator (MSO) and Local Cable Operator (LCO).

4. In this connection a consultation paper was issued on 22.12.2011 on the “Issues related to Implementation of Digital Addressable Cable TV Systems”. In response to the consultation paper released on 22nd December 2011, a total of 87 comments and 4 counter-comments were received from stakeholders including consumers. Subsequently, an Open House Discussion (OHD) was also held on 13th March 2012, where the issues were discussed at length, with the stakeholders present. Based on the comments/views of the stakeholders and the analysis, various provisions related to the tariff and composition of BST, retail tariff, tariff for advertisement free channels and revenue share between MSO and LCO have been worked out and, accordingly, the tariff order has been amended through this tariff amendment order.

II. Analysis of issues

A. Basic Service Tier

5. Many stakeholders have suggested that the stipulation already available in the Tariff Order dated 21st July 2010, should be replicated for the DAS areas instead of a provision of BST, as the same is adequate to safeguard consumers’ interests. The said provision allows the operator of an addressable TV platform to prescribe a minimum subscription charge, not exceeding Rs. 150 per subscriber per month, towards the channels chosen by the consumer, on a-la-carte or bouquet basis. In support of their view, the stakeholders have stated that the fast paced growth of DTH, especially in the rural areas and cable dark areas, clearly establishes that market forces have worked extremely well at the retail, both in terms of packaging and pricing. As far as essential public services are concerned, some of the stakeholders have stated that the services of the Public broadcaster meets the public’s needs for basic television services across the country in the form of FTA Channels through its terrestrial service and DTH platform (DD Direct plus) without any recurring charges.

6. Section 4A of the Cable Television Networks (Regulation) Amendment Act 2011, provides for a basic service tier (BST) which is a package of free to air channels to be offered by a cable operator, for a single price to subscribers of the area in which his cable television network is providing service. The subscriber has the option for subscribing to BST. The composition and tariff of the BST are to be fixed by TRAI. Thus the tariff order provides the prescription related to BST.
7. As far as the size and rate of the BST is concerned, different prescriptions have been suggested by the stakeholders. Majority of the stakeholders who have suggested the size of the BST, have kept it in the range of 30 to 70 channels with price ranging from Rs. 60 to Rs. 150. A few stakeholders have also suggested slab wise BST prescription ranging from Rs. 82 for upto 30 channels to Rs. 150 for more than 100 channels. Some of the other stakeholders have also suggested that India being a diverse country with respect to ethnicity, language, preferences, tastes and choices, it would be prudent that size as well as its rate should be left to be decided by operators, rather than it being defined by the Authority. One suggestion was that, in line with the international markets wherein 70-80 channels are being offered by the operators without forced regulation, in India also, the offerings in the other platforms will compel the DAS operator to offer a competitive proposition for the BST.
8. As per the extant provisions applicable to the notified CAS areas, a minimum of thirty FTA channels are to be included in the package of channels forming BST which the cable operator need to supply to all the consumers of his cable network, at a maximum amount of Rs. 82/- (excluding Taxes) per subscriber per month. In the non-CAS areas, as per the TRAI's tariff order dated 1st Oct 2004, as amended from time to time, if the operator provides only FTA channels then it should be provided to the subscriber at a maximum of Rs. 82/- per subscriber per month (excluding Taxes) for a minimum of 30 FTA channels. The tariff order also prescribes ceilings of slab wise subscription rates for the bundled packages (of pay and FTA channels), based on a minimum of 30 FTA channels mandatorily included in each of these bundled packages. Similarly, in the draft tariff order which forms a part of a comprehensive report on tariff issues, concerning the non-CAS areas, submitted by TRAI on 21st July 2010, to the Hon'ble Supreme Court, three uniform ceilings for the bundled offerings, across the country,

have been prescribed wherein a minimum 30 FTA channels are to be mandatorily included in each bundled offering. The tariff (maximum) has been kept at Rs. 100/- for a minimum 30 FTA channels, if the operator offers only FTA channels to the consumers. Further, in all the above tariff stipulations, any FTA channel, over and above the mandatory minimum limit of 30 channels, is to be offered to the consumer without any additional charges.

9. It is a fact that digitization enables to overcome the channel carrying capacity constraints. While in analog mode only one channel could be carried in a 7MHz/8 MHz channel, in digital mode, depending upon the compression and modulation techniques employed, 10-15 channels can be carried in a single 7MHz/8 MHz channel. Also, more channels are now available in the market. Accordingly, it is expected that the BST should include substantially more number of channels as compared to that earlier mandated. However, inclusion of more channels will naturally pushup the cost of the BST. Moreover, prescribing a very large BST will limit the flexibility to carry other offerings. Therefore, these aspects have to be suitably balanced while prescribing the size and the rate of the BST. Accordingly, the Authority has prescribed that a minimum of 100 FTA channels be offered as BST by all the operators of digital addressable cable TV systems at a maximum amount of Rs. 100/- (excluding taxes).
10. On the issue of composition of the BST, a large majority of the stakeholders are of the view that the BST should have a mix of channels of different genres and the composition should be left to be decided by the market forces in accordance with the choice, preference and requirements of the subscribers in the local area of operation and preference be accorded to the regional channels while forming the BST. The Authority is of the view that the operator shall compose and offer BST having an equitable mix of various genres by providing a minimum of five channels from each genre. However, in case, sufficient number of channels of a particular genre are not available, the same can be complemented by the operator with channels of other genres. It has also been provided that the operator should offer the channels of Prasar Bharati, the Public broadcaster, namely DD- Bharati, DD-Malyalam, DD-Podhigai, DD-Odiya, DD-Bangla, DD-Saptagiri, DD-Chandana, DD- Sahyadri, DD- Girnar, DD-Kashir, DD-NE , DD-Punjabi, within the 100 channels of the BST. This is expected to benefit those consumers who are residing/working at places, far away from their native places.

152050712-5

11. On the issue, whether the price prescription and the size of the BST be different for different states, cities or towns, though some of the stakeholders have said that it should be different for different areas but a large majority has said that the rate and size of the BST should be kept same throughout the country. The Authority recognizes that accounting for varying affordability levels of the consumers and their choices would not be possible due to variance in affordability and choice, even within localities in a city, or even within the same locality serviced by a single operator. A uniform prescription, on the other hand, provides for the consumer protection at an aggregate level, and is easy to enforce and communicate to the consumers. In line with the suggestion of the majority of the stakeholders, the Authority has decided that the size and rate of the BST to be kept the same, throughout the country.

12. The amended Cable TV Act provides that the FTA channels offered in the BST shall also have to be offered by the operator in a-la-carte form, at a tariff to be fixed by TRAI. A mixed response has been received from the stakeholders on the a-la-carte channels price of the channels forming the BST. Some of the stakeholders, including few Broadcasters, MSOs and DTH operators, few individual consumers, a consumer organization, majority of the LCOs and a cable operators Association, have stated that it should not be mandated on account of technical and commercial feasibility, inconvenience for the consumer to choose from a very large number of available channels and also as inferred from the studies carried out in international markets etc. However, many stakeholders have supported provision of channels in a-la-carte form and have suggested the a-la-carte channel rates based on linkage with the average channel price in the BST (with a-la-carte rates at 0-10% above the average BST channel rate) or fixed rates ranging from Rs. 1.5 to Rs. 5, with the majority lying between Rs. 2 to Rs. 3 per channel per subscriber per month.

13. The technology provides the consumers to choose channels, and to avail the benefit of addressable digitization, the Authority has decided that the consumer may opt for the BST of minimum 100 FTA channels (including the channels of public broadcaster, Prasar Bharati) offered by the operator or may choose 100 channels of his liking, from the FTA channels carried over the cable network of the operator, at the charges of the BST. The subscriber has the option not to opt for any FTA channel or BST.

B. Retail tariff

14. On the issue of retail tariff the views of the majority of the stakeholders are polarized around broadly three propositions- i) retail tariff be based on the CAS model, ii) retail tariff be linked with the ceilings prescribed at the wholesale level and iii) retail tariff be kept under forbearance.

15. The stakeholders who have suggested to adopt tariff model as prevalent in the notified CAS areas, are of the view that this system has been working well for last more than 5 years and none/minimal litigations amongst the service providers have been witnessed and the consumers are also satisfied with this model of tariff. Some of these stakeholders have suggested that suitable provisions may be added in this model for the HD and niche channels. They have suggested that HD channels may be offered at say 15% above the channel rate ceiling of Rs. 5.35 and the niche channels may be kept under forbearance.

16. Some of the stakeholders are of the view that when the wholesale rates have been regulated, the retail rates should also be regulated and there could be a linkage between the channel rates offered at the wholesale by the broadcasters to the operator of the addressable platform and the retail rates offered by the operator to the consumers. Ideally the linkage should be determined by the carriage cost incurred plus the profit margin and accordingly, the retail channel rates have been prescribed by various stakeholders in the range of 10% to 100% above the wholesale rate of the channel. A few stakeholders have also specified the range of channel rates at the retail level as Rs 6 to Rs. 7 for pay channels and around Rs.2 to Rs. 3 for the FTA channels, which they have stated to be kept common for all the genres whereas other few stakeholders have suggested different ceilings, for both pay and FTA channels, ranging between Rs. 3 to Rs. 10 for channels of different genres.

17. The stakeholders who have advocated forbearance at the retail level have stated that the forbearance at the retail level has worked well in the DTH sector and in support of their argument they have cited the growth trajectory of the DTH services, both in the urban as well as in the rural areas,. It has been argued by these stakeholders that DAS, being a competing

platform with the DTH and IPTV, the same tariff regime be prescribed to maintain level playing field amongst various addressable TV platforms.

18. The instruments of addressability, a-la-carte choice to the consumer and availability of sufficient competition from other addressable platforms provide adequate checks and balances over the forbearance of retail pricing, wherein packaging and pricing is being determined by the operators. Additionally, forbearance at the retail level for DAS areas would maintain level playing field amongst various addressable TV platforms. Accordingly, the Authority has decided to continue with forbearance at the retail level tariff for the DAS areas also. However, in case of FTA channels, as there is no content cost involved, the Authority is of the view that the channel pricing at the retail level, as decided by the operator of the digital addressable system for his network, should be uniform for all the FTA channels.

C. A-la-carte provisioning of the channels

19. As far as the consumer is concerned, primary benefit to the consumer that an addressable TV system provides is the ability to choose the channels of his choice. In the tariff order dated 21st July 2010, the operators are mandated to offer all the pay channels carried over their network, on a-la-carte basis. Around 75% of all the channels, permitted by the Ministry of Information and Broadcasting, are FTA channels. Thus, offering only the pay channels on a-la-carte basis, largely deprive the subscribers from exercising their choice of channels. Therefore, the Authority feels it appropriate to extend the a-la-carte provisioning of channels to cover both the FTA and pay channels carried over the network of an operator as it is technically feasible and does not burden much the operator logically on the one hand and empowers the consumers to benefit from the digitization with addressability of the TV services distribution sector, on the other hand. However, the advantages of bundled packages of channels should also be available to the subscriber. Subscribers should be able to choose between a-la-carte channels or bouquets or a combination of the two. This is likely to ensure the co-existence of bouquets with a-la-carte offerings on addressable systems. Accordingly, the provision of bouquet of channels to the subscribers is also a part of the Tariff Order.

20. While mandating a-la-carte choice of channels to the subscriber, the Authority recognizes the fact that if changes in choices made by subscribers are too frequent, service providers may face technical and operational difficulties. In order to provide a measure of stability to the service providers in servicing the choices made by the subscribers, the provision wherein the service providers can stipulate a minimum commitment period for the a-la-carte choice of channels by the subscriber, has been retained.

D. Twin conditions at retail level

21. TRAI had, in its Tariff Orders dated 21st Nov. 2006, for commercial subscribers in CAS and non-CAS areas, made a provision wherein twin conditions were defined to establish a relationship between the a-la-carte rate of a channel and the rate of the bouquet wherein this channel forms a part. The conditions were introduced to ensure that the consumer is not made to subscribe to bouquet(s) and left with no choice to choose. These conditions ensure that the individual channel choice is not illusory. These conditions act as a check on increase in channels prices and pricing of bouquets to make the choice illusory.

22. While prescribing the a-la-carte provisioning in the tariff order dated 21st July 2010, the Authority had decided to adopt a light touch approach and not to mandate any conditions on pricing of a-la-carte channels. It was stated in the explanatory memorandum that the Authority would, however, keep a close watch over the market and may intervene in public interest whenever necessary. In this context, in the DTH sector wherein the operators are allowed to package and price the offerings, it has been observed that the uptake of channels on a-la-carte basis is negligible. One of the prime reasons for poor uptake of a-la-carte channels is that the a-la-carte rates of the channels are disproportionately high as compared to the bouquet rates, especially in the entry level packs.

23. Further, the popular channels are distributed among different packs, both at entry level and in other smaller additional packs. As a result, the subscriber is often compelled to take additional packs to meet his demand, ultimately ends up paying more. Thus, the main purpose of addressability is defeated and ills of non-addressability continues. To ensure choice to the consumers through a-la-carte offering and to prevent skewed a-la-carte pricing, the twin

conditions have been extended to the retail level pricing. It is expected that the twin conditions at the retail level would allow a consumer to effectively exercise his choice through rational pricing of channels in a-la-carte vis-a-vis bouquet pricing. For the existing operators of the digital addressable systems, a period of 60 days has been provided for the compliance of these twin conditions.

E. Minimum Monthly Subscription Charges

24. The viability and sustainability of the distributors' operations also needs to be kept in mind. In the tariff order dated 21st July 2010, a provision exists which allows the operators to specify a minimum monthly subscription for availing the services of such service provider. This in a sense represent, the minimum monthly subscription charges that the operators expect to collect from the subscribers to recover the cost of providing the services.

25. During the consultation process industry stakeholders have emphasised that in the cable sector there is a sizable population of consumers which has a limited paying capacity. For such subscribers the Authority is of the view that the minimum monthly subscription charges of Rs. 150 (maximum) may be a potential entry barrier. Therefore, the Authority has decided that, instead of a single minimum monthly subscription option, the service provider of the digital addressable cable TV systems shall specify at least two minimum monthly subscription options. One option wherein the service provider can specify a minimum monthly subscription, not exceeding Rs. 100 per subscriber, and the other one wherein the operator can specify this amount, to be not exceeding Rs. 150 per subscriber per month. In the first minimum monthly subscription option (not exceeding Rs. 100 per month), the subscriber can avail the BST or any 100 channels on a-la-carte basis from the FTA channels carried by the MSO in its network. In case the subscriber opts for one or more pay channels, with or without BST or other FTA channels, the operator can charge him as per the second minimum monthly subscription option (not exceeding Rs. 150 per month). As far as other addressable platforms are concerned, the existing stipulation concerning the minimum monthly subscription option has been retained.

F. Provisions related to change in composition of package/pricing

26. To protect the consumer interests, a provision has been made in the Tariff Order dated 21.07.2010, that the operator shall not increase the charges for a subscription package offered by him, for a minimum period of six months from the date of enrolment of the subscriber for such subscription package. However, operators have requested to make amendment in this provision so that in case one or more FTA channels forming part of the package gets converted to pay channel, adherence to this provision should not put unnecessary burden on the operators to carry such channels without charging the consumers. Accordingly, realising the difficulty faced by the operators, a proviso has been added to the relevant clause which allows the operator to either drop the particular channel(s) from the package or modify the charges accordingly, based on the discretion of the consumer.

G. Revenue share

27. Most of the broadcasters/aggregators suggested that the revenue share between operators of digital addressable cable systems should be based on the mutual negotiation instead of being regulated by TRAI. Some of them have suggested that the revenue share of BST should be regulated by TRAI whereas rest of the offerings should be on mutual negotiation and in case the revenue share is defined by TRAI, it should be same for both the BST and other offerings. Some of broadcasters have suggested a maximum of 15-20% share for LCO while one suggestion is that the revenue be shared in the ratio of 55:45 for MSO and LCO respectively. Most of the industry associations have also favoured that the revenue share should be based on mutual negotiation.

28. The MSOs are divided on mechanism for determining the subscription revenue share between the MSO and LCO. Some have suggested that it should be based on mutual negotiation while others have suggested that it should be defined by TRAI. It has been suggested that the revenue share could be on similar lines as CAS model with a higher revenue share for MSOs, keeping in view the investments the MSOs have to make in the DAS areas. Almost all the LCOs are in favour of regulation of subscription revenue share by TRAI. Some of them have suggested that the current CAS regime should be followed for DAS as well. Different ratios have been

suggested by the LCOs for BST (ranging between 75% to 100% in favour of LCO) and rest of the offerings (varying from 25-60% in favour of LCO).

29. TRAI in its tariff order dated 21st July 2010, had prescribed that the revenue share between the MSO and LCO should be decided through mutual negotiations. During the consultation process as well as at various industry fora, it has been emphasised that the Authority should define the revenue share in order to protect level playing field and interests of the large cable community. It has also been stated that the revenue share for the basic service tier amount should also be clearly apportioned between the LCO and MSO.

30. In the digital addressable cable TV systems, the subscriber management system (SMS) of the MSO contains database regarding the subscriber base and the channels/bouquets subscribed by each of its subscribers. This database is verifiable and auditable. Also, the MSO is mandated to declare the a-la-carte rates of all the channels and the rates of bouquets/packs offered by it, if any. With these details, the exact subscription revenue is also known to the MSO as well as to the LCOs connected to the MSO. In view of the transparency inbuilt into the digital addressable systems, the Authority is of the view that it would be appropriate that the MSO and LCO share the subscription revenue, based on mutual negotiations, as the parameters to negotiate upon are no longer disputable. In case, they fail to arrive at a mutually agreed revenue share arrangement, they shall share the subscription revenue as prescribed in Part IV of this tariff order.

31. A large number of stakeholders have advocated for adoption of revenue share model of the notified CAS areas. In the notified CAS areas, for the pay channels, the subscription revenue is shared amongst the broadcaster, MSO and LCO in the ratio of 45:30:25 respectively. The revenue share mechanism based on CAS model has been considered by the Authority. Even though, this formulation for revenue share cannot be applied directly in the DAS areas, wherein the MSO defines the retail price of the channel/bouquets instead of the broadcaster, some useful clue can be drawn from the same. In the digital addressable cable TV systems, the FTA channels (as well as pay channels) are to be aggregated by the MSO and carried in digital and encrypted form. They are duly accounted and authorised through the SMS system of the MSO, and carried over the network of both the MSO and LCO. This is akin to carriage of pay channels in the notified CAS areas. Therefore, as far as the quantum of revenue share for the FTA

channel/bouquets is concerned, the CAS formulation can be adopted. Being FTA channels, there is no share for the broadcasters and so the revenue share works out to be 55:45 between the MSO and LCO respectively.

32. As far as pay channels and bouquets, having pay channels, are concerned, the MSO would be required to pay the broadcaster from its share of the subscription revenue. This requires that his share should be more than the revenue share of 55%, prescribed for the BST/FTA channels (a-la-carte or bouquets). In the notified CAS areas, the revenue share of 25% for the pay channels for the LCOs, was prescribed in the backdrop that LCO would keep the total subscription revenue arising out of the BST. In the Digital Addressable Cable TV Systems, the subscription revenue arising out of the BST and FTA channels (a-la-carte or bouquet(s)) is going to be shared with the MSOs in the ratio of 55:45 (MSO:LCO). So one argument could be that the LCO is required to get more revenue out of the pay channels and bouquet having pay channels, to sustain their business. In this regard, the main difference between the CAS and the DAS is that, in CAS the FTA channels were downlinked by LCO and distributed whereas in DAS all channels, including FTA channels, are downlinked, encrypted and distributed by the MSO. In case of the bouquet having both pay and FTA channels, as it would be very difficult to bifurcate the pay and FTA channel revenue components, it would be prudent to share the revenue for such bouquet(s) in the same ratio as that for the pay channels. Further, to incentivise the LCO, to promote pay channels on a-la-carte basis, a better revenue share for the LCOs is envisaged which would ultimately ensure better choice to the consumer. So there is a case to have a revenue share higher than 25% for LCOs for pay channels or bouquet with pay channels. For only FTA subscription (a-la-carte, bouquet or BST), it is now 45%. So taking a mid path i.e. 35% for LCOs, for pay channels or bouquet with pay channels, is expected to generate sufficient revenue for LCOs. This would leave 65% of subscription revenue with the MSOs. Besides the subscription revenue, the MSO has other sources of revenue in the form of carriage fee. Also, the retail packaging and pricing would be done by the MSO in the DAS regime. Keeping in view all these factors, the Authority has decided that the subscription revenue shall be shared between the MSO and LCO in the ratio of 65:35 respectively, for the pay channels and bouquet having pay channels, with or without FTA channels.

H. Advertisement free channels

33. On the issue of viability of ad-free channels, many stakeholders have opined that ad-free channels are viable, however, a large majority of the stakeholders, consisting of all the segments of the stakeholders including the consumers, are of the view that the determination of viability of the ad-free channels in the Indian markets be left to the market forces to decide.

34. On the issue of tariff dispensation for the ad-free channels, a large majority of the stakeholders have advocated forbearance at both the wholesale and retail levels in the DAS areas. Few MSOs have, however, suggested that the wholesale tariff be regulated, keeping the retail under forbearance whereas one cable operator association has suggested that tariff for ad-free channels should be regulated by TRAI.

35. As far as the sharing of the subscription revenue of the ad-free channels is concerned, all the broadcasters have viewed that it should be left for the commercial negotiations between the service providers. The other stakeholders are divided over this issue. Some of these stakeholders have suggested that revenue share be decided in the same way as any other pay channel while others have suggested different percentages for broadcaster, MSO and LCO, however, they have not offered any justification for the same.

36. Offering of a channel in advertisement-free format (Ad-free channel) is a recent phenomenon in the Indian television market. These channels are driven by demand and generally cater to targeted segment of viewers. The ad-free channels, being solely dependent on the subscription revenue and demand based, in line with the view of a large majority of the stakeholders, the Authority has decided to keep the ad-free channels under complete forbearance. The niche channels e.g. HDTV channels and 3D channels, which require specialized STBs, are already under forbearance and would continue to remain under forbearance. The Authority will review the position at an appropriate time. As far as revenue share is concerned, it shall be shared between MSO and LCO in the same ratio as defined for other channels.